

जन जागरूक एवं कल्याण योजना (JJKY)

नईदिशा पब्लिक सर्विसेज, पटना द्वारा संचालित

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी तथा लाभ घर-घर तक पहुंचाना।

www.naidisha.in

योजना क्या है -

जब किसी देश/राज्य के समक्ष आवश्यकताएँ अनन्त हो, उनकी पूर्ति के संसाधन सीमित हो तो वैसे में आवश्यकता होती है योजनावद्ध विकास की। अतः सीमित संसाधनों के माध्यम से देश की तात्कालीन आवश्यकताओं के लिए निर्धारित प्राथमिकता के क्रम में तीव्रतर विकास हेतु किया गया प्रयत्न ही योजना है।

योजना का उद्देश्य - सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करना है जिससे समावेशी विकास संभव हो सके। सरकार द्वारा लागू योजनाओं के उद्देश्यों को इस प्रकार गतिमान करना है कि सामाजिक तथा व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित हो सके।

अनियोजित समाज में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं, यह आवश्यक नहीं है कि सभी शक्तियाँ एक ही दिशा में कार्य करे। कुछ शक्तियाँ प्रभावी होती हैं और कुछ उद्योगात्मी। सरकार के चार शब्दों पर गौर करने की आरजू है। वे शब्द हैं, - 1. योजना, 2. अभियान, 3. अधिकार और 4. आन्दोलन। इसमें योजना और अभियान सरकार चलाती हैं। जबकि अधिकार और आंदोलन का संबंध साधारण आम जनता से है।

भारत में योजना लागू करने में चार सामाजिक आर्थिक उद्देश्य हैं-

1. उत्पादन को बढ़ाना ताकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सके।
2. पूर्ण रोजगार प्रदान करना।
3. आय तथा सम्पत्ति की असमानताओं को समाप्त करना।
4. सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना।

योजना प्रारंभ-1920 ई0 में अंग्रेज द्वारा प्रथम योजना, प्रथम प्रोजेक्ट गुडगाँव प्रोजेक्ट चलाया गया। 1921 ई0 में बंगाल टैगोर इन्डूज (इंग्लैंड) के द्वारा श्री निकेतन योजना शिक्षा के लिए चलाया गया।

जैसे-जैसे जरूरतें महसूस की गयी वैसे-वैसे ही सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया। उन्हीं योजनाओं को **जन जागरूक एवं कल्याण योजना (JJKY)** द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी तथा लाभ घर-घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार की योजनाओं की सूची

- 1. प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2019 | लघु व्यापारी मानधन योजना** लॉन्च की तारीख : 23 जुलाई 2019
उद्देश्य : व्यापारियों, स्वरोजगारियों को 3,000 रुपये महिना पेंशन
राष्ट्रीय पेंशन योजना या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 के अंतर्गत सरकार प्रतिमाह 3,000 रुपये निश्चित पेंशन 60 वर्ष की आयु होने पर देगी। इस सरकारी योजना से देश भर में लगभग 3 करोड़ व्यापारियों, स्वरोजगारियों को लाभ पहुंचेगा। व्यापारियों, स्वरोजगारियों के लिए प्रतिमाह 3 हजार रुपये वाली इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने प्रीमियम राशि (PM Laghu Vyapari Maan-dhan National Pension Scheme Premium Amount) का भी प्रावधान किया है जो लाभार्थी की आयु के अनुसार लिया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : <https://maandhan.in>
- 2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY Farmers Pension Scheme)** लॉन्च की तारीख : 1 जून 2019
उद्देश्य : किसानों को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन
पीएमकेएमवाई की घोषणा यूनियन बजट 2019-20 में की गयी थी, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 हजार रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। आधिकारिक वेबसाइट : <https://maandhan.in> या <https://pmkmy.gov.in/>
- 3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019** लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2019
उद्देश्य : किसानों को सालाना 6,000 रुपये
इस पीएम किसान आय सहायता योजना (Farmers Income Support Scheme) के तहत मोदी सरकार छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उन्हें प्रतिवर्ष 6000 रुपये वित्तीय सहायता देती है। पीएम किसान योजना 2019 (PM Kisan Scheme) जो किसानों के कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो उनको न्यूनतम आय का आश्वासन देगी। आधिकारिक वेबसाइट : <https://pmkisan.gov.in>
- 4. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना** लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2019
उद्देश्य : असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों को 3000 रुपये पेंशन
सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार, वर्कर भारतीय जीवन बीमा निगम योजना (Life insurance corporation - LIC) की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maan-dhan Yojana) के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों / कामगारों को 3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट : <https://labour.gov.in/pm-sym>
- 5. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (PMRSSM)** लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018
उद्देश्य : गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार | आधिकारिक वेबसाइट : <https://www.pmjay.gov.in/>
- 6. प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान** लॉन्च की तारीख : 23 सितंबर 2018
उद्देश्य : PMJAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा
आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नगदीरहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार
पूरी जानकारी : पीएम जन आरोग्य अभियान
- 7. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)**
उद्देश्य : अल्पसंख्यक लोगों तक केन्द्रीय व राज्य की सभी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना और उनको मुख्यधारा में लाना। आधिकारिक वेबसाइट : <http://www.minorityaffairs.gov.in/>
पीएम जन विकास कार्यक्रम से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ कर उनका विकास करना

8. कृषोन्नति योजना – हरित क्रांति

लॉन्च की तारीख : 11 मई 2016

उद्देश्य : किसानों की आय में वृद्धि करना | आधिकारिक वेबसाइट : <http://agriculture.gov.in>

कृषोन्नति योजना – हरित क्रांति का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है और कृषि क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता का विकास करना है इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है – MIDH, NMOOP, NMSA, SMAE, SMSP, SMAM, SMPPQ, IMACES, ISAC, ISAM, NeGP-A जो किसानों का हर तरह से विकास करेंगी।

09. राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना (N-YES)

लॉन्च की तारीख : 17 जुलाई 2018

उद्देश्य : सभी कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना

राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना (N-YES) के पहले चरण में सभी 10वीं और 12वीं के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें उन्हें वेतन भी दिया जाएगा।

10. वन धन योजना

लॉन्च की तारीख : 14 अप्रैल 2018

उद्देश्य : आदिवासी लोगों के लिए वनों तक सुविधाएं पहुंचाना और वनों का विस्तार करना केंद्र सरकार ने वनों के विस्तार के लिए 115 जिलों में काम भी शुरू कर दिया है जिससे आदिवासी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके और वनों में पेड़-पौधों को काटना भी ना पड़े और इसके लिए सरकार ने 3,000 वन केंद्र भी स्थापित कर दिये हैं।

आधिकारिक वेबसाइट : <https://ngodarpan.gov.in/>**11. NMSA के तहत राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन**

लॉन्च की तारीख : 25 अप्रैल 2018

उद्देश्य : बांस के उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय को बढ़ाना | आधिकारिक वेबसाइट : <https://nbm.nic.in/>

राष्ट्रीय बांस मिशन से सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर बांस की खेती को बढ़ावा देना जिससे की किसानों की आय तो बढ़े ही साथ में छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों का ध्यान बांस की खेती की ओर हो।

12. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

लॉन्च की तारीख : 2008-09

उद्देश्य : रोजगार को बढ़ावा देना और रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना | वेबसाइट : <http://kviconline.gov.in/>

पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से खुद का रोजगार विकसित करने में सहायता करने के साथ-साथ रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना और छोटे, मध्यम व लघु व्यापार में वृद्धि करना।

13. पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी

स्कीम लॉन्च की तारीख : 23 अप्रैल 2018

उद्देश्य : श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना पूरे देश में पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम से श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना जिससे उनके जीवन को आसान बनाया जा सके।

आधिकारिक वेबसाइट: <https://labour.gov.in/>**14. शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFEL)**

लॉन्च की तारीख : 1 अप्रैल 2009

उद्देश्य : छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे वे अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से कर सके।

आधिकारिक वेबसाइट : <http://www.ncgtc.in/>**15. राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS & NAPS)**

लॉन्च की तारीख : 19 अगस्त 2016

उद्देश्य : राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेंटिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्योगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है।

आधिकारिक वेबसाइट : <http://apprenticeship.gov.in/> or <http://mhrdnats.gov.in/>

16. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2019

लॉन्च की तारीख : जून 2015

उद्देश्य : नियोक्ताओं व उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना जिससे की वे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर सकें।

17. केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (CSIS)

लॉन्च की तारीख : अप्रैल 2009

उद्देश्य : छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे उन्हें उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने में किसी भी तरह की वित्तीय समस्या का सामना ना करना पड़े। आधिकारिक वेबसाइट : <http://mhrd.gov.in/>

18. फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना

लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018

उद्देश्य : कृषि संबंधी क्षेत्र में तकनीकों का विकास करना जिससे हवा में प्रदूषण को कम करना और फसल में पोषक तत्वों को सुधारना। आधिकारिक वेबसाइट : <https://farmech.dac.gov.in>

19. ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (डीटीसी) योजना

लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018

उद्देश्य : ड्राइवरों को ड्राइविंग स्किल को बढ़ाना जिससे रोड के ऊपर दुर्घटना की संभावना कम हो और ड्राइविंग के क्षेत्र में रोजगार बढ़ सके। सभी वाणिज्यिक क्षेत्र के ड्राइवरों को इस योजना से जोड़ना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है।

आधिकारिक वेबसाइट : <http://morth.nic.in/>**20. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान)**

लॉन्च की तारीख : 8 मार्च 2018

उद्देश्य : कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्म हुए बच्चों की बीमारियों से निपटने के लिए पोषण अभियान के तहत, सभी किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों (6 महीने से 3 साल तक) को पका हुआ भोजन मिलेगा। वे घर पर राशन ले सकते हैं जो कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्मे बच्चे और स्टंटिंग की समस्या से निपटेंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल योजना है जो कुपोषण को जड़ से खत्म करेगी। यह "कुपोषित मुक्त भारत" के सपने को साकार करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : <https://www.icds-wcd.nic.in/nnm/home.htm>

21. प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना (PMRF)

लॉन्च की तारीख : 5 मार्च 2018

उद्देश्य : पीएचडी के लिए फेलोशिप प्रोग्राम देश में प्रतिभाशाली छात्रों को पीएचडी करने के लिए आईआईटी और आईआईएस जैसे संस्थानों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करना। आधिकारिक वेबसाइट : <https://pmrf.in/>

22. सौर चरखा योजना

लॉन्च की तारीख : 5 फरवरी 2018

उद्देश्य : महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देना सौर चरखा योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे इन यंत्रों को इस्तेमाल करना है जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और खादी के वस्त्र वाले क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्य लक्ष्य सौर चरखा योजना से ग्रीन ऊर्जा को तो बढ़ावा मिलेगा ही जिसे प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों पर भी दबाव कम होगा। इसके साथ ही छोटे, मध्यम व लघु उद्योगों को भी आगे बढ़ने में सहायता होगी।

23. आर्थिक आरक्षण - कम आय वालों के लिए 10% कोटा

लॉन्च की तारीख : 7 जनवरी 2019

उद्देश्य : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को 10% आरक्षण प्रदान करना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी से गरीब बच्चों को 10% आर्थिक आरक्षण देना शुरू किया है। यह आरक्षण ओबीसी / एससी / एसटी बच्चों द्वारा प्राप्त कोटा के समान है।

24. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)

लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018

उद्देश्य : किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप देना वेबसाइट : kusum.online or <https://mnre.gov.in/#> कुसुम सौर पंप योजना 2019-20 में किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दिये जाते हैं जिससे की ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली की पहुँच बहुत कम है या फिर दूर दराज के इलाके जहां पर बिजली की समस्या रहती है। इसके अलावा किसानों का डीजल पंप पर होने वाला खर्च भी कम होगा और यह उनकी आय को वर्ष 2022 तक दुगना करने में भी मदद करेगी।

25. गोबर धन योजना**लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018****उद्देश्य :** गोबर प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार करना और उनको ऊर्जा में कैसे बदलना इस पर विचार करना

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गोबर धन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत मवेशियों को गोबर के प्रबंधन और पुनः उपयोग करने में मदद मिलेगी और इस तरह से राष्ट्र "ओपन शौच फ्री" होगा। किसान इस कचरे को कृषि में खाद और उर्वरक के रूप में पुनः उपयोग कर सकते हैं। 2018-19 के केंद्रीय बजट में इस कृषि केंद्रित योजना से ग्रामीणों के जीवन में सुधार होगा। गोबर धन का मतलब जैविक जैव-एगो संसाधन धन है। यह योजना मवेशियों के गोबर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसे जैव ईंधन / बायो-CNG के रूप में इस्तेमाल करेगी। उसी प्रकार से, यह योजना केंद्रीय सरकार का एक और कदम है जिसे "2022 तक किसानों की आय दुगुनी होगी"

26. रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र सब्सिडी योजना**लॉन्च की तारीख : 29 जनवरी 2018****उद्देश्य :** रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना

अब सामाजिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र के सभी लोग सोलर रूफटॉप कनेक्शन को अपनी छतों पर लगवा सकते हैं। इस योजना में, लोगों को MNRE रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कनेक्शन योजना के तहत कुल लागत पर 30% सब्सिडी मिलेगी। जिससे उनका बिजली का बिल कम हो सकता है। आधिकारिक वेबसाइट : <https://mnre.gov.in/>

27. महिला स्वाभिमान अभियान**लॉन्च की तारीख : 27 जनवरी 2018****उद्देश्य :** स्त्री स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए CSC की पहल

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने CSC के माध्यम से स्त्री स्वाभिमान पहल की शुरुआत की है। CSC द्वारा महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह एक अनूठी पहल है। इस योजना के तहत, सरकार महिलाओं को पर्यावरण के अनुकूल माहवारी पैड प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल मुख्य रूप से "महिला सशक्तीकरण" पर ध्यान केंद्रित करेगी। रवि शंकर प्रसाद (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कानून एवं न्याय मंत्री) और अल्फांस कन्ननथानम (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और पर्यटन राज्य मंत्री - आईसी) इस पहल की शुरुआत करेंगे।

आधिकारिक वेबसाइट : <http://streeswabhiman.in/>**28. खेलो इंडिया स्कूल गेम्स****लॉन्च की तारीख : 31 जनवरी 2018****उद्देश्य :** स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों को ढूँढना और उन्हें 5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना

खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है। यह स्कूल स्तर पर खेलों का आयोजन करके किया जाएगा और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इस प्रशिक्षण में, सरकार 5 लाख रुपये प्रदान करेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : <http://kheloindia.gov.in/>

29. सबला योजना**लॉन्च की तारीख : 27 सितंबर 2010**

उद्देश्य : केंद्र सरकार इससे किशोरियों का सशक्तीकरण करना चाहती है जिससे किशोर बालिकाओं (एसएजी) के लिए स्कीम में 10 से 14 वर्ष की आयु की सभी स्कूली लड़कियों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस योजना से ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (ARSH) के बारे में जागरूकता पैदा करना है। वेबसाइट : <http://wcd.nic.in/schemes/scheme-adolescent-girls-sag>

30. बाजार आश्वासन योजना**लॉन्च की तारीख : 27 दिसम्बर 2017****उद्देश्य :** किसानों के लिए मूल्य समर्थन

सरकार ने किसानों की खराब स्थिति के चलते ग्रामीण किसानों के लिए मूल्य समर्थन सुनिश्चित कर सकते हैं इसी के लिए केंद्र सरकार ने बाजार आश्वासन योजना को शुरू किया था जिसके माध्यम से सरकार राज्य सरकार को 30% मुआवजा प्रदान करती है अगर खरीद में किसी तरह का नुकसान होता है तो। इस योजना से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

31. सृष्टि योजना**लॉन्च की तारीख : 22 दिसम्बर 2017****उद्देश्य :** छतों पर सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए प्रोत्साहन

यह सोलर पावर प्लांट सब्सिडी योजना रूफटॉप पर लोगों को सोलर प्लांट लगवाने पर सब्सिडी प्रदान करेगी। जिससे लोगों को एक साफ, शुद्ध ऊर्जा की ओर जागरूक किया जा सके। इससे पर्यावरण तो प्रदूषण से मुक्त होगा ही साथ में लोगों को बिजली के बिल से भी मुक्ति मिलेगी।

32. वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना (SCBTS)**लॉन्च की तारीख : 21 दिसम्बर 2017****उद्देश्य :** वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार

वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की इस योजना में SCBTS राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे इस क्षेत्र में ट्रेनिंग पाकर लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं या फिर वस्त्र व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ सरकार ने वेतन देने का प्रबंधन भी रखा है। इस योजना से माध्यम, लघु उद्योगों को भी विस्तार मिलेगा।

33. दलितों के लिए अंतरजातीय विवाह योजना**लॉन्च की तारीख : 7 दिसम्बर 2017****उद्देश्य :** दलितों से शादी पर 2.5 लाख रुपये अनुदान

अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ बीआर अंबेडकर योजना को संशोधित कर अंतरजातीय विवाह योजना में लाया गया है। इस योजना के तहत, सरकार 2.5 लाख रुपये प्रदान करती है पर शर्त यह है की दूल्हा, दुल्हन में से कोई एक दलित होना अनिवार्य है।

34. प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना**लॉन्च की तारीख : 29 नवंबर 2017****उद्देश्य :** पावरलूम बुनकरों को वित्तीय सहायता

सभी पावरलूम बुनकरों को अब उनके काम के लिए 90% वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना के तहत पावरलूम क्षेत्र के सभी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन भी किया जाएगा। यह लघु उद्योगों (SAATHI) की योजना में मदद करने के लिए कुशल वस्त्र प्रौद्योगिकियों के सतत और त्वरित गोद लेने के द्वारा किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 20% मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी। लॉन्ग टर्म लोन की सुविधा भी सिर्फ 6% ब्याज पर उपलब्ध होगी।

35. प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना**लॉन्च की तारीख : 9 अगस्त 2017****उद्देश्य :** अल्पसंख्यक लड़कियों को 51000 रुपये आर्थिक सहायता

शादी शगुन योजना एक नई आगामी केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के तहत सभी ग्रेजुएट मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लड़कियों को 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता शादी के उपहार के रूप में प्रदान की जायेगी। मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां जो अपनी शादी से पहले किसी भी वर्ग में अपनी ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं वो इस शादी शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य होंगी।

36. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना**लॉन्च की तारीख : सितंबर 2017****उद्देश्य :** सभी नागरिकों को बिजली का कनेक्शन

ग्रामीण और शहरी इलाकों के सभी घर जो अभी भी बिजली रहित हैं उन्हें बिजली प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने सौभाग्य - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए 16,320 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान 1,000 दिनों के भीतर सभी 18,452 गांव जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली प्रदान करने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आज देश में केवल 3,046 गांव ही ऐसे हैं जहाँ बिजली अभी नहीं पहुंची है। वेबसाइट : <http://saubhagya.gov.in/>

37. उदय या राइज योजना**लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018****उद्देश्य :** सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था का विकास

RISE योजना शैक्षणिक संस्थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था के विकास के लिए कम लागत की धनराशि प्रदान करेगा। स्कूलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त संस्थान (सीएफआई) सहित उच्च शिक्षण संस्थान सरकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए नए स्कूल भी खोलेगा और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देगा

38. राष्ट्रीय वयोश्री योजना**लॉन्च की तारीख : बजट 2015-16****उद्देश्य :** वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना

राष्ट्रीय वयोश्री योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक नई योजना है। इस सरकारी योजना के तहत केंद्र सरकार BPL परिवारों से सम्बन्ध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन को आसान बनाने के लिए मुफ्त सहयोगी उपकरणों की पेशकश करेगी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 477 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जाएगी और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक शिविर में 25 मार्च को शुरू होगी। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार मुफ्त सहायक उपकरण जैसे कान की मशीन, व्हीलचेयर और कई अन्य उपकरण प्रदान करेगी।

39. प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना**लॉन्च की तारीख : 22 नवंबर 2017****उद्देश्य :** महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन

केंद्र सरकार ने देश में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना शुरू की है जिसके तहत सरकार ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त करेगी ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन लागू की जाएगी। यह योजना 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। पूरे देश के 161 जिलों में बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ (BBBP) पहल के सफल कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार ने इस योजना के लाभों के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना के लिए 2017-18 से 2019-20 के दौरान 3,636.85 करोड़ रुपये की वित्तीय परिव्यय प्रदान करेगी। केंद्र सरकार, राज्य और जिला स्तर पर एक "एक सामान्य कार्य बल" का गठन करेगी। यह कार्य बल आयोजन योजना की समीक्षा और निगरानी में मदद करेगा ताकि कार्रवाई और लागत दक्षता का अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके।

40. प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY)**लॉन्च की तारीख : 13 दिसम्बर 2016****उद्देश्य :** अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने की योजना

प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने और उन्हें विदेशों में रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए एक नई आगामी योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की तरह ही, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से नई योजना भी लागू की जाएगी। विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) योजना के कार्यान्वयन के लिए परामर्श निकाय होंगे। आधिकारिक वेबसाइट : <https://www.msde.gov.in/>

41. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान**लॉन्च की तारीख : 9 जून 2016****उद्देश्य :** गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच

पीएमएसएमए योजना देश भर में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देगी। सभी गर्भवती महिलाओं को उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनकी गर्भावस्था के 4 महीने बाद किट व पैकेज मुहैया कराया जाएगा। यह नए जन्मे बच्चे के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करेगा। महीने की प्रत्येक 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार भी प्रदान किया जाएगा। यह मातृ मृत्यु दर को कम करेगा और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों / बीमारियों के बारे में जागरूक करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : <https://pmsma.nhp.gov.in/>

42. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)**लॉन्च की तारीख : 7 अक्टूबर 2017****उद्देश्य :** ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल क्रांति से अवगत कराना

PMGDISHA योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सूचना, ज्ञान, कौशल के साथ सशक्त बनाना और उन्हें शासन में भाग लेने में सक्षम बनाना है। कंप्यूटर, डिजिटल उपकरणों (टैबलेट, स्मार्टफोन) को संचालित करने, ई-मेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने, एक्सेस करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सेवाएं, सूचना की खोज, डिजिटल भुगतान करना आदि। आधिकारिक वेबसाइट : <https://www.pmgdisha.in/>

43. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना**लॉन्च की तारीख : 18 अप्रैल 2017****उद्देश्य :** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास

SAMPADA योजना "कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत 7 योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण क्षमता (यूनिट स्कीम) का निर्माण / विस्तार, कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, पिछड़े और आगे के लिंक का निर्माण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन और संस्थान आदि हैं।

आधिकारिक वेबसाइट : <http://mofpi.nic.in/Schemes/pradhan-mantri-kisan-sampada-yojana>**44. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना****लॉन्च की तारीख : अगस्त 2017****उद्देश्य :** गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये सहायता

पीएमएमवीवाई या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। पीएमएमवीवाई गर्भावस्था सहायता योजना के तहत, केंद्र सरकार 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं और बच्चे के पहले जन्म के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं को 6000 रुपये सहायता लेने के लिए PMMVY पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ेगा। 6000 गर्भावस्था सहायता प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) या निकटतम अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आवेदन पत्र सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है या PMMVY गर्भावस्था सहायता योजना आवेदन फॉर्म महिला और बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : <http://www.wcd.nic.in/node/712776>

45. समग्र शिक्षा अभियान**लॉन्च की तारीख : 28 मार्च 2018****उद्देश्य :** सभी शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को एक योजना में जोड़ना

सरकार ने इसमें मुख्यतः 3 मौजूदा शिक्षा योजनाओं - सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को मर्ज करने के लिए समागम शिक्षा अभियान शुरू किया है। यह योजना राज्यों को प्री-नर्सरी से कक्षा 12 वीं तक स्कूली शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा है। आधिकारिक वेबसाइट : <http://samagra.mhrd.gov.in/>

46. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)**लॉन्च की तारीख : 2005****उद्देश्य :** ग्रामीण लोगों को 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार | वेबसाइट : <http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx>

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना (MNREGA Yojna) पूरी तरह से रोजगार पर केंद्रित एक सरकारी योजना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 देश के गरीब परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करता है जिनमें जॉब कार्ड धारक या NREGA लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की डीटेल शामिल होती है। हर साल प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक नया नरेगा जॉब कार्ड तैयार किया जाता है जिसे लाभार्थी आसानी से मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर nrega.nic.in पर देख सकता है। NREGA job card list 2019 का उपयोग करके आप अपने गांव / शहर के लोगों की पूरी सूची देख सकते हैं जो आगामी वित्तीय वर्ष में MGNREGA के तहत काम करेंगे। हर साल नए लोग NREGA job card list में जोड़े जाते हैं और कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर हटा भी दिए जाते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो नरेगा के योग्यता और मानदंड को पूरा करता है वह NREGA Job Card के लिए आवेदन कर सकता है।

47. ई बस्ता प्रोजेक्ट**लॉन्च की तारीख : अगस्त 2015****उद्देश्य :** डिजिटल कंटेंट की पहुँच सुनिश्चित करना। आधिकारिक वेबसाइट : <https://www.ebasta.in/>

यह एक ऑनलाइन डिजिटल मंच है जहाँ सभी शिक्षक, प्रकाशक, छात्र ई-लर्निंग के लिए एक साथ आते हैं। बस्ता का मतलब है स्कूल बैग में जैसे होता है वैसे ही स्कूल की किताबों और अध्ययन सामग्री का डिजिटल संस्करण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। ई-बुक्स को टैबलेट और कंप्यूटर पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रकाशक पोर्टल में सामग्री अपलोड कर सकते हैं और प्रबंधित भी कर सकते हैं। इस ऐप को आप गूगल प्लेस्टोर से स्मार्टफोन व टैबलेट पर डाउनलोड कर सकते हैं।

48. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)**लॉन्च की तारीख : 28 अगस्त 2014**

उद्देश्य : वित्तीय समावेशन और देश के सभी घरों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बनाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) देश के सभी घरों में व्यापक वित्तीय समावेशन लाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। PMJDY के तहत, कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका बैंक में बचत खाता नहीं है, वह ज़ीरो बैंक बचत खाता खोल सकता है। यह योजना वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग / बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बीमा और पेंशन जैसी सेवाओं को किफायती तरीके से सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों जिनका बैंक में खाता नहीं है उन्हें बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। वेबसाइट : <http://www.pmjdy.gov.in>

49. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)**लॉन्च की तारीख : 8 अप्रैल 2015****उद्देश्य :** सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता

गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनंस एजेंसी) शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) देश भर की सभी बैंक शाखाओं से उपलब्ध है। छोटे व्यवसाय / स्टार्टअप या उद्यमी अपना कारोबार शुरू करने के लिए 50 हजार से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : <http://www.mudra.org.in>

50. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना**लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015****उद्देश्य :** सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा उपलब्ध कराना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुँच को बढ़ाना है। यह योजना 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 330 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का जीवन बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : <http://www.jansuraksha.gov.in>

51. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना**लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015****उद्देश्य :** सभी भारतीय नागरिकों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना | वेबसाइट : <http://www.jansuraksha.gov.in>

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुँच को बढ़ाना है और उन्हें दुर्घटना के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 12 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

52. अटल पेंशन योजना**लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015****उद्देश्य :** सभी तरह की पेंशन योजनाओं में लोगों की संख्या को बढ़ाना वेबसाइट : <http://www.jansuraksha.gov.in>

अटल पेंशन योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई तीन जन सुरक्षा योजनाओं में से एक है। APY का उद्देश्य पूरे देश में पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से निजी असंगठित क्षेत्र को लक्षित है और 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 60 वर्षकी आयु प्राप्त करने और प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 वर्ष के लिए अंशदान देना होगा। यह योजना 1000 रुपये से 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान करती है।

53. प्रधानमंत्री आवास योजना

लॉन्च की तारीख : 25 जून 2015

उद्देश्य : सभी नागरिकों को 2022 तक आवास घर देना

वेबसाइट : <http://mhupa.gov.in>

प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएमएवाई के तहत, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लोगों को लगभग 5 करोड़ किफायती घर मुहैया कराए जाएं। शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है और देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ घर देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही इन घरों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने कम ब्याज के लोन की सुविधा भी रखी है।

54. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

लॉन्च की तारीख : 11 अक्टूबर 2014

उद्देश्य : भारी बारिश, प्राकृतिक आघातों, कीटों या बीमारियों से किसानों को फसल बीमा प्रदान करना है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद देश के नागरिकों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएँ शुरू करी थीं। जिनमें से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) जिसको 18 फरवरी, 2016 को लॉन्च किया गया था। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं में से सबसे सफल योजना थी, जिसके तहत भारी बारिश, प्राकृतिक आघातों, कीटों या बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान होने पर केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आघात पीड़ित किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी प्रीमियम राशि जान सकते हैं। केंद्र सरकार सफलतापूर्वक पूरे देश में इस सरकारी योजना को चला रही है। पीड़ित किसान खरीफ और रबी की फसलों के लिए पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खुले हैं।

आधिकारिक वेबसाइट : <https://pmfby.gov.in/>**55. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)**

लॉन्च की तारीख : अप्रैल 2015

उद्देश्य : गरीबों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करना और देश भर में ज्यादा से ज्यादा गरीब आबादी तक पहुंचना। गरीब कल्याण योजना एक गरीबी उन्मूलन योजना है, जो मुख्य रूप से गरीबों के हित के लिए काम करेगी। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाएगा और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करना और प्रेरित करना है।

आधिकारिक वेबसाइट : <http://niti.gov.in>**56. मेक इन इंडिया**

लॉन्च की तारीख : 25 सितंबर 2014

उद्देश्य : बहु-राष्ट्रीय, साथ ही घरेलू कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने और 25 क्षेत्रों में रोजगार और कौशल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। केंद्र सरकार का मेक इन इंडिया पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। इस पहल से भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश के लिए देश विदेश की कंपनी को आकर्षित करना है। आधिकारिक वेबसाइट : <http://www.makeinindia.com>

57. स्वच्छ भारत अभियान

लॉन्च की तारीख : 2 अक्टूबर 2014

उद्देश्य : महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना

स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास मंत्रालय (एम / ओ यूडी) और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः पियजल और स्वच्छता मंत्रालय (एम / ओ डीडब्ल्यूएस) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसके तहत देश में जगह-जगह सफाई अभियान चलाये जाते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : <http://swachhbharat.mygov.in>

58. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

लॉन्च की तारीख : 17 फरवरी 2015

उद्देश्य : किसानों को अपने खेतों के लिए पोषक तत्वों / उर्वरक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देकर उनके खेतों की उत्पादक क्षमता में सुधार करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य का अध्ययन और समीक्षा करना है जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता का पूर्ण मूल्यांकन हो सके जैसे पानी और पोषक तत्वों की सामग्री और अन्य जैविक गुणों की पहचान की जा सके। अगर किसी तरह की उजाड़ क्षमता में किसी तरह की कमी मिलती है तो एक किसान को इसे बेहतर करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए यह सब बताया जाता है। वेबसाइट : <http://www.soilhealth.dac.gov.in>

59. स्किल इंडिया**लॉन्च की तारीख : 16 जुलाई 2015****उद्देश्य :** 2022 तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को अलग-अलग तरह की स्किल में प्रशिक्षण देना

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेंटिसशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें उम्मीदवार उद्योगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है। वेबसाइट : <http://skillindia.gov.in>

60. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना**लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015**

उद्देश्य : देश में बेटियों की कम जन्म दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान की शुरुआत करी थी जिससे की आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की लिंग अस्थिरता ना आए, इसके लिए जगह-जगह जागरूकता अभियान भी चलाये जाते हैं। इसके अलावा बेटी के जन्म के समय वित्तीय सहायता भी दी जाती है जिससे की उसकी शादी और पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। आधिकारिक वेबसाइट : <http://wcd.nic.in>

61. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY)**लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015**

उद्देश्य : गरीब परिवारों से ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके, समावेशी विकास प्राप्त करना। डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार प्रदान करना। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्लस्टर पहलों में से एक है जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है – मिशन फॉर गरीबी में कमी जिसे आजीविका कहा जाता है। आधिकारिक वेबसाइट : <http://ddugky.gov.in>

62. कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT)**लॉन्च की तारीख : 24 जून 2015**

उद्देश्य : घरों में बुनियादी सेवाएं (जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करना और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का उद्देश्य – AMRUT योजना यह है कि (i) सुनिश्चित करें कि हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल अवश्य होना चाहिए (ii) हरियाली और अच्छी तरह से बनाए रखने वाले खुले स्थानों (जैसे पार्कों) के विकास से शहरों का सौहार्दपूर्ण मूल्य बढ़ता है (iii) गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के लिए सार्वजनिक परिवहन या निर्माण सुविधाओं पर स्विच करना जिससे प्रदूषण में कमी आ सके। आधिकारिक वेबसाइट : <http://amrut.gov.in>

63. उड़ान योजना**लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014**

उद्देश्य : उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए एक मंच प्रदान करना जिससे की छात्राओं को सशक्त बनाया जा सके और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने के अवसर प्रदान किए जा सके। यह एक तरह की छात्रवृत्ति योजना है जिससे मेधावी छात्राओं को बिना किसी कठिनाई के स्कूलों से तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके क्योंकि पैसों और सलाह की कमी के कारण वे अपनी आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती यह योजना उन्हें ऐसा करना के लिए स्वतंत्र बनाएगी। आधिकारिक वेबसाइट : <http://mhrd.gov.in>

64. स्टार्टअप इंडिया / स्टैंड अप इंडिया योजना**लॉन्च की तारीख : 16 जनवरी 2016**

उद्देश्य : केंद्र सरकार स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित कर रही है। उम्मीदवार startupindia.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन कर सकते हैं। यह सरकारी योजना भारत में व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्टार्ट अप बिजनेस को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया योजना के लाभों में DIPP recognition, Learning program, नए बिजनेस के लिए सरकार की योजनाओं को शामिल करना, विशेषज्ञों के साथ जुड़ना आदि है। इस पहल का मुख्य फोकस युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और बेरोजगार युवाओं को जॉबसीकर से उद्यमी बनाना है। आधिकारिक वेबसाइट : startupindia.gov.in

65. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (NSTSS)

लॉन्च की तारीख : 20 फरवरी 2015

उद्देश्य : 8 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों के बीच खेल प्रतिभा को पहचानने के लिए।

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत स्कूलों से 8-14 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभाशाली छोटे बच्चों को हाजिर करने और उन्हें वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें पोषण देने के लिए यह योजना लागू की गई है। आधिकारिक वेबसाइट : <http://www.sportsauthorityofindia.nic.in>

66. राष्ट्रीय गोकुल मिशन

लॉन्च की तारीख : 16 दिसम्बर 2014

उद्देश्य : देसी गोजातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए। आधिकारिक वेबसाइट : <http://dahd.nic.in>

राष्ट्रीय गोकुल मिशन का लक्ष्य एक केंद्रित और वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी नस्लों का संरक्षण और विकास करना है। यह 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास के लिए एक परियोजना है। जिससे स्वदेशी गाय और अन्य गोवंश को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई थी।

67. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

लॉन्च की तारीख : 1 मई 2016

उद्देश्य : केंद्र सरकार ने सभी गरीब परिवारों को राहत देते हुए फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना को बढ़ा दिया है। अब यूनिवर्सल पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana Scheme) देश के सभी राशन कार्ड धारकों पर 17 दिसंबर 2018 से लागू होगी। सरकार के इस कदम से बाकी के बचे हुए गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए फ्री गैस कनेक्शन मिल जाएगा। सरकारी एलपीजी गैस कनेक्शन योजना (PMUY LPG Connection Yojana) के तहत सरकार हर गैस कनेक्शन पर 1600 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। इस सब्सिडी राशि में सिलेंडर की फीस और फिटिंग

का खर्च शामिल है। Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ने PMUY Scheme को बढ़ाने की मंजूरी इसलिए दी क्योंकि देश में अभी भी बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। वे सभी लोग जो अभी तक मौजूदा लाभार्थी सूची में शामिल नहीं थे उन्हें भी अब लाभार्थी सूची (Free LPG gas connection beneficiary list) में शामिल किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : <http://www.pmujiwalayojana.com>

68. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

लॉन्च की तारीख : 24 अप्रैल 2018

उद्देश्य : पंचायत राज संस्थानों को सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए। यह केंद्रीय वित्त बजट 2016-17 में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा घोषित एक नई प्रस्तावित योजना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 655 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए थे। आधिकारिक वेबसाइट : <http://rgsa.nic.in>

69. सुरक्षित मातृत्व आसवासन सुमन योजना

लॉन्च की तारीख : 10 अक्टूबर 2019

उद्देश्य : गर्भवती महिला, नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच व दवाएँ

केंद्र सरकार ने माता और नवजात बच्चे की मृत्यु दर को जीरो करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आसवासन सुमन योजना (Surakshit Matritva Aashwasan – SUMAN scheme) को 10 अक्टूबर 2019 गुरुवार को लॉन्च कर दिया है। सुमन योजना 2019 (Central Govt. SUMAN Scheme) में गर्भवती महिलाओं, माताओं को प्रसव के 6 महीने बाद और बीमार नवजात शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं (Free healthcare benefits to Pregnant Women) का लाभ मिल सकेगा। इस सरकारी योजना से मोदी सरकार का मानना है कि देश में इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आएगी।

सुरक्षित मातृत्व आसवासन सुमन योजना 2019 (Central Govt. SUMAN Scheme) के तहत लाभार्थी महिलाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों (Health Scheme for Pregnant Women) पर जा कर सेवा का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। इसमें नियमित प्रसव जांच के साथ महिला के शरीर में विटामिन, आइरन, कैल्सियम की जांच भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा अभियान के तहत चेकअप, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, टेटनस डिप्थीरिया इंजेक्शन और व्यापक एएनसी पैकेज के अन्य घटक और घर पर जाकर शिशु की जांच शामिल की गई है।

आधिकारिक वेबसाइट : <https://mohfw.gov.in>

70. निर्यात ऋण विकास निर्विक योजना**लॉन्च की तारीख : 18 सितंबर 2019**

उद्देश्य : मोदी सरकार निर्विक योजना से निर्यातकों (Loan Scheme for Exporters, MSMEs) के लिए ऋण उपलब्धता को बढ़ाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को इस योजना की घोषणा करी। इस सरकारी योजना को एक्सपोर्ट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शुरू करेगी। एनआईआरवीआईके योजना के तहत निर्यातकों को आसानी से लोन दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री निर्विक योजना 2019 ('NIRVIK' scheme for Exporters) से एमएसएमई क्षेत्र के निर्यातकों के मॉडरेशन के लिए काम किया जाएगा जिससे एक्सपोर्ट गारंटी बढ़ाई जा सके और इसके तहत मूलधन और ब्याज का 90% तक बीमा के तहत कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री निर्विक योजना (NIRVIK Yojana) के अनुसार अगर कोई नुकसान होता है तो ईसीजीसी (Export Credit Guarantee Corporation Loan scheme – ECGC) ने लगभग 60% तक की ऋण गारंटी प्रदान की है जिसके तहत निर्विक उपभोक्ताओं व निर्यातकों को 90% तक कवर दिया जा सकेगा। आधिकारिक वेबसाइट : <https://www.ecgc.in/>

71. समर्थ योजना**लॉन्च की तारीख : 2017**

उद्देश्य : लोगों के लिए कपड़ा निर्माण क्षेत्र में वस्त्र मंत्रालय की फ्री प्रशिक्षण स्कीम

समर्थ योजना (Textile Sector Samarth Scheme) के तहत वस्त्र मंत्रालय आगामी महीनों में 4 लाख लोगों को कपड़ा क्षेत्र में ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगी। इस सरकारी योजना से टेक्सटाइल सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण (Free training in Textile Sector) के लिए 18 राज्यों के करीब चार लाख लोगों को चुना जाएगा। समर्थ योजना 2019 के कार्यान्वयन (Implementation of SAMARTH Scheme) के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समर्थ योजना (Free Skill training in Samarth Scheme) का मुख्य उद्देश्य हथकरघा, हस्तशिल्प, सेरीकल्चर और जूट के पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल को विकसित करना और आगे बढ़ाना है। वस्त्र मंत्रालय की यह समर्थ योजना लोगों में स्व-रोजगार को भी बढ़ावा देगी। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हुए समझौतों में 16 राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिनमें जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। आधिकारिक वेबसाइट : <https://samarth-textiles.gov.in>

72. 1 देश 1 राशन कार्ड योजना**लॉन्च की तारीख : 10 अगस्त 2019**

उद्देश्य : केंद्र सरकार ने 4 राज्य तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र-गुजरात में 1 देश 1 राशन कार्ड योजना की करी शुरुआत, इन राज्यों के लोग ले सकेंगे किसी भी राज्य से राशन, 1 जून 2020 से पूरे देश में होगी लागू

आधिकारिक वेबसाइट : mofpi.nic.in

73. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना**लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2018**

उद्देश्य : ईएसआईसी बेरोजगार होने की स्थिति में बीमित कर्मचारियों को नकद में राहत राशि प्रदान करेगी

यदि कोई कर्मचारी कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं और अटल बीमित कल्याण योजना के तहत नई नौकरी खोजते हैं तो कर्मचारियों को नौकरी मिलने तक सहायता मिलेगी। यदि बीमित व्यक्ति (आईपी) बेरोजगार है तो सरकार पिछली चार योगदान अवधि (चार योगदान अवधि / 730 के दौरान कुल कमाई) के दौरान प्रति दिन की कमाई का औसत 25% की सीमा तक राहत प्रदान करेगी, आईपी पर जीवनकाल में एक बार अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी का भुगतान किया जाएगा जिसके लिए शपथ-पत्र के रूप में दावा करना अनिवार्य है। वेबसाइट : <http://www.esic.in/employeeportal/login.aspx>

74. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना**लॉन्च की तारीख : 5 जुलाई 2019**

उद्देश्य : नीली क्रांति की होगी शुरुआत

पीएम मत्स्य सम्पदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) से मोदी 2.0 सरकार देश को जलीय उत्पादों के लिए केन्द्रीकरण करके हॉटस्पॉट में बदलना चाहती है। इस सरकारी योजना से देश में मछलीपालन या फिर जलीय उत्पादों के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनको राहत मिलेगी। यूनियन बजट 2019-20 में पीएम किसान संपदा योजना (PM Kisan Sampada Scheme – PKSS) का उद्देश्य जलीय कृषि को बढ़ावा देना है जिससे जलीय क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ाया जा सके और व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए ऋण की पहुँच को मछुआरा समुदायों तक आसान बनाया जा सके। मोदी सरकार सभी मछुआरों को किसानों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाएँ और समाज कल्याण योजनाओं (Pradhan mantri Farmer Welfare & Social Security Schemes) के अंतर्गत लाना चाहती है जिससे दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवरेज दिया जा सके।

75. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण**लॉन्च की तारीख : 2015**

उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को अपने आवास प्रदान करना। आधिकारिक वेबसाइट : <http://mohua.gov.in/cms/rera.php>
ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जिन भी लोगों के पास अपना घर नहीं है उनको अपना खुद का आवास देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना नई लिस्ट शहरी, ग्रामीण 2019-20 (PMAY Urban, Gramin Beneficiary New List) की लाभार्थी सूची में अपना नाम PMAY App के माध्यम से भी देख सकते हैं। PMAY सूची में नाम और अपना विवरण देखने के लिए 4 तरीके हैं, विवरण की जांच करने के लिए, लोगों को आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पंजीकरण आईडी की आवश्यकता होगी।

76. उन्नत भारत अभियान**लॉन्च की तारीख : 25 अप्रैल 2018**

उद्देश्य : ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना। वेबसाइट : <http://unnatbharatabhiyan.gov.in/>
उन्नत भारत अभियान के तहत, सरकार एक समावेशी भारत की वास्तुकला का निर्माण करने में मदद करने के लिए ज्ञान संस्थानों की मदद लेगी। यह योजना जैविक खेती, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, कारीगरों, उद्योगों और आजीविका, बुनियादी सुविधाओं, अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करेगी।

77. टीबी - क्षय रोग मुक्ति योजना**लॉन्च की तारीख : 28 अक्टूबर 2014**

उद्देश्य : 2020 तक टीबी की बीमारी को पूर्ण रूप से खत्म करना

टीबी मिशन 2020 के तहत, सरकार ने टीबी निदान के लिए वाणिज्यिक धारा विज्ञान पर प्रतिबंध लगाने जैसे नियामक कदम उठाए हैं और दवाओं पर राष्ट्रीय कानून की एक अलग अनुसूची के तहत टीबी विरोधी दवाएं भी लाई गयी हैं। जब भी नया टीबी मामला सामने आएगा, यह मिशन दुरुपयोग और अनिवार्य अधिसूचना को रोक देगा।

आधिकारिक वेबसाइट : <https://www.nhp.gov.in/disease/respiratory/lungs/tuberculosis>

78. धनलक्ष्मी योजना**लॉन्च की तारीख : 22 दिसम्बर 2017**

उद्देश्य : बालिकाओं को नकद प्रोत्साहन राशि। वेबसाइट : <https://wcd.nic.in/schemes/dhanalakshmi>

धनलक्ष्मी योजना मुख्य रूप से एक बीमा कवर प्रदान करने के माध्यम से भारत में कन्या भ्रूण हत्या के मामलों को कम करने के लिए केंद्रित है। यह योजना बालिकाओं के लिए शिक्षा का भी समर्थन करती है और बाल विवाह को रोकने के लिए आकर्षक बीमा योजनाएं प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह के मामलों को कम करके माता-पिता को एक आकर्षक बीमा कवर प्रदान करना और माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, बालिकाओं के लिए विभिन्न चिकित्सा व्यय शामिल किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जीवन को महत्व देना था और उन्हें एक दायित्व के रूप में नहीं माना गया था।

79. विद्यांजली योजना**लॉन्च की तारीख : 16 जून 2016**

उद्देश्य : विद्यांजलि योजना का उद्देश्य सरकारी और प्राथमिक स्कूलों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। सर्व शिक्षा अभियान के समग्र तत्वावधान में विद्यांजलि योजना शुरू की गई है। विद्यांजलि स्वयंसेवक कार्यक्रम के तहत, भारतीय डायस्पोरा, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों सहित सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों, सेवानिवृत्त पेशेवरों और महिलाएं जो घर निर्माता हैं, एक के लिए अनुरोध करने वाले स्कूल में स्वयंसेवक बन सकते हैं। वेबसाइट : <https://mygov.in/task/vidyanjali-school-volunteer-programme/>

80. स्टैंड अप इंडिया योजना**लॉन्च की तारीख : 5 अप्रैल 2016**

उद्देश्य : महिलाओं और अनुसूचित जाती, जनजाति के लोगों के लिए उद्यमी विकास करना

स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम मूल रूप से देश के निचले वर्गों अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, जनजातियों और महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार की एक पहल है। Stand up India Scheme के तहत Scheduled caste (SC), Schedule tribe (ST) और महिलाओं के बीच रोजगार को बढ़ावा देना है। जिससे की वे इस योजना के अंतर्गत लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकें। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) या कम से कम एक महिला को अपना कारोबार स्थापित करने के लिए लोन देना है। आवेदक अपना व्यवसाय लगाने के लिए बैंक की शाखा से 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक से लोन ले सकता है। आधिकारिक वेबसाइट : <https://www.standupmitra.in/>

81. ग्राम उदय से भारत उदय**लॉन्च की तारीख : 28 मार्च 2016****उद्देश्य : ग्राम स्वशासन अभियान****आधिकारिक वेबसाइट : rural.nic.in**

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्देश्य गांवों में सामाजिक समरसता बढ़ाने, पंचायती राज को मजबूत करने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और किसानों की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी प्रयास करना है। सरकार की यह योजना सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगी।

82. सामाजिक अधिकारिता शिविर**लॉन्च की तारीख : 29 जून 2017****उद्देश्य : दिव्यांग लाभार्थियों को सहायता देना और सहायक उपकरण प्रदान करना**

सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्देश्य उन तरीकों को देखना है जिनके माध्यम से नवाचार और प्रौद्योगिकी दिव्यांग बहनों और भाइयों के जीवन को बदला जा सके। इस पहल के तहत, सरकार विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सहायता और अन्य सहायता उपकरण प्रदान करती है। आधिकारिक वेबसाइट : socialjustice.nic.in

83. विद्यालक्ष्मी लक्ष्य योजना**लॉन्च की तारीख : 15 अगस्त 2015****उद्देश्य : विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण योजना**

विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लक्ष्य लेने वाले छात्रों के लिए अपनी तरह का पहला पार्टल है। यह पार्टल वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। इस पार्टल को एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और रखरखाव किया जा रहा है। छात्र पार्टल पर पहुंचकर कहीं भी, कभी भी बैंकों को शिक्षा ऋण के आवेदन देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : <https://www.vidyalakshmi.co.in/Students/>

84. स्वयं प्रभा योजना**लॉन्च की तारीख : 15 अगस्त 2015****उद्देश्य : विद्यार्थियों के लिए शिक्षा लक्ष्य उपलब्ध कराना**

SWAYAM PRABHA 32 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण उपलब्ध कराती है। हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए राज नई सामग्री उपलब्ध होगी जो एक दिन में कम से कम 5 बार दोहराई जाएगी। स्वयंवर प्रभा छात्रों को उनकी सुविधा का समय चुनने की अनुमति देती है। चैनल BISAG, गांधीनगर से अपलिक किए गए हैं। एनपीटीईएल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी और एनआईओएस द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है। INFLIBNET सेंटर वेब पार्टल का रखरखाव करता है।

आधिकारिक वेबसाइट : <https://www.swayamprabha.gov.in/index.php/home>**85. उड़ान - उड़े देश का हर नागरिक योजना****लॉन्च की तारीख : 15 जून 2016****उद्देश्य : क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना**

UDAN योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हवाई यात्रा को सस्ता बनाने के लिए शुरू किया गया है, जो आम नागरिकों को हवाई यात्रा कराने के लिए शुरू की गई थी। उद्योग चैंबर फिक्की के अनुसार, देश भर में लगभग 44 हवाई अड्डों पर योजना के तहत परिचालन निष्पादित करने की क्षमता है।

भौगोलिक, परिचालन और वाणिज्यिक मापदंडों के आधार पर 414 में से 44 रेखांकित और बिना लाइसेंस के हवाई अड्डों की सूची तैयार की गई है, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क योजना UDAN का हिस्सा होने की संभावना है। रिपोर्ट में महानगरों, राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक, औद्योगिक और पर्यटन केंद्रों सहित लघु हवाई अड्डों के लिए लगभग 370 संभावित स्थलों की सूची का भी उल्लेख किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट : civilaviation.gov.in

86. डिजिटल गाँव योजना**लॉन्च की तारीख : 21 मई 2018****उद्देश्य : गाँवों के विकास के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए**

डिजिटल विलेज योजना का उद्देश्य गाँवों में शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा की सस्ती पहुँच प्रदान करना है। ग्राम आधारित कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) वाई-फाई चौपाल का प्रबंधन करेगा और लोगों के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचे और इंटरनेट की पहुँच प्रदान करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : digitalindia.gov.in

87. एक भारत श्रेष्ठ भारत**लॉन्च की तारीख : सितंबर 2018**

उद्देश्य : एकीकृत और विकसित भारत बनाना है।

आधिकारिक वेबसाइट : ekbharat.gov.in/

एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता कायम करना है और हमारे देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक बंधनों को बनाए रखना और मजबूत करना है। सभी भारतीय राज्यों के बीच एक गहन और संरचित जुड़ाव के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा देना।

88. अमृत योजना (AMRIT)**लॉन्च की तारीख : 15 नवंबर 2015**

उद्देश्य : सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराना और प्रत्यारोपण की सर्जरी को सस्ता बनाना। आधिकारिक वेबसाइट : mohfw.gov.in
सस्ती दवाओं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (AMRIT) – नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का एक प्रयास है कि कैंसर, हृदय और अन्य बीमारियों के उपचार पर रोगियों द्वारा किए गए खर्च को कम किया जाए। इन AMRIT आउटलेट्स पर आम लोगों के लिए 60-70 फीसदी की छूट दर पर दवाएं उपलब्ध होंगी।

89. डिजिटल व्यापार योजना**लॉन्च की तारीख : 15 दिसम्बर 2016**

उद्देश्य : विक्रेताओं के लिए डिजिटल पेमेंट की प्रणालियों का विकास करना

डिजी धन पुरस्कार व्यापार योजना व्यापारियों के लिए है जो डिमोनेटाइजेशन के बाद भुगतान के डिजिटल तरीकों के माध्यम से भुगतान करना है जिससे उनके लिए अलग-अलग विधियों का विकास किया जा सके और उन्हें भुगतान से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे भुगतान सीधा बैंक खाते में होता है। योजना में 50 रुपये से 3,000 रुपये तक के बीच कशलेस लेनदेन को कवर करेगी जिससे गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। आधिकारिक वेबसाइट : digidhanlucky.mygov.in

90. भीम ऐप (BHIM UPI)**लॉन्च की तारीख : 2016**

उद्देश्य : एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) सुविधा प्रदान करना। आधिकारिक वेबसाइट : गूगल प्लेस्टोर

BHIM (Bharat Interface for Money) यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर आधारित नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित एक मोबाइल भुगतान ऐप है। इस ऐप का उद्देश्य 2016 के भारतीय बैंक नोट के विमुद्रीकरण के भाग के रूप में बैंकों के माध्यम से सीधे ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करना और कशलेस लेनदेन की दिशा में लोगों को प्रोत्साहित करना है। ऐप उन सभी भारतीय बैंकों का समर्थन करता है जो UPI का उपयोग करते हैं, जो कि तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) बुनियादी ढांचे पर बनाया गया है और उपयोगकर्ता को किसी भी दो दलों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग सभी मोबाइल उपकरणों पर किया जा सकता है।

91. जविक खेती योजना**लॉन्च की तारीख : 17 मार्च 2018**उद्देश्य : किसानों के बीच जविक खेती को बढ़ावा देना। आधिकारिक वेबसाइट : jaivikkheti.in

पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में जविक खेती / jaivik kheti को बढ़ावा देने के लिए एक नया Jaivik Kheti पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल रसायन मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा देगा और खेती के उद्देश्य के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। तदनुसार, यह पोर्टल महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजनाओं – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), परम्परागत कृषि विकास योजना, सूक्ष्म-सिंचाई और एमआईडीएच के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

92. महिला सशक्तिकरण योजना**लॉन्च की तारीख : 8 मार्च 2018**उद्देश्य : महिला उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान करना। आधिकारिक वेबसाइट : wep.gov.in

NITI Aayog ने महिला उद्यमियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर वे अपनी टलेंट और विचारों विचारों को उद्यम में बदल सकती हैं जिससे आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की भागीदारी भी देश के निर्माण में और ज्यड़ा बढ़ेगी। यह पोर्टल 3 स्तंभों – शिक्षा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति पर बनाया गया है।

93. सेवा सहायता केंद्र – नमो योजना**लॉन्च की तारीख : 6 मार्च 2018****उद्देश्य :** गरीब लोगों के लिए नमो योजना के तहत सेवा सहायता केंद्र | आधिकारिक वेबसाइट : india.gov.in

नमो योजना केंद्र योजना का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न वन स्टॉप सेंटर खोलना है ताकि वे सरकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी एकत्र कर सकें और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। नमो योजना केंद्रों पर से केंद्र सरकार की लगभग 112 योजनाएँ जोड़ी जाएंगी। गरीब और दलित लोग इन केंद्रों पर अपने प्रश्नों और शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और ऐसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

94. मातृत्व लाभ प्रोत्साहन योजना**लॉन्च की तारीख : 17 नवंबर 2018****उद्देश्य :** 26 सप्ताह के मातृत्व लाभ के लिए सरकार का नया कदम | आधिकारिक वेबसाइट : labour.gov.in

श्रमिक और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने सभी गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ प्रोत्साहन योजना (Maternity Leave Incentive Scheme) के बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया है क्योंकि मीडिया के कुछ हिस्सों में इस योजना के बारे में कुछ गलतफहमी फैलाई जा रही थी जैसे की इस प्रस्ताव के वर्तमान चरण में मातृत्व लाभ योजना को मंजूरी मिल गई है। हालांकि, इस योजना के लिए जो आवश्यक बजट है उसकी फ़ाइनल अधिकारियों के पास मंजूरी के लिए गई हुई है। कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि इस योजना को श्रम कल्याण विभाग द्वारा फंड से चलाया जाएगा। जिससे श्रम कल्याण विभाग के ऊपर 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Act), 1961 केवल उन संस्थानों पर लागू होता है जो कारखानों, खदानों, वृक्षारोपण, दुकानों, अन्य संस्थाओं में जहां 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यदि इस प्रस्तावित योजना को मंजूरी मिलती है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश की हर महिला के पास रोजगार, पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण समान रूप से पहुंचे।

95. प्रधानमंत्री वरुण मित्र योजना**लॉन्च की तारीख : 1 जनवरी 2019****उद्देश्य :** 21 दिन फ्री ट्रेनिंग के बाद मिलेगी नौकरी | आधिकारिक वेबसाइट : mnre.gov.in

वरुण मित्र योजना के तहत सरकार तीन हफ्ते की फ्री ट्रेनिंग देगी। सरकार का कहना है की फ्री ट्रेनिंग स्कीम से बेरोजगारों को 21 दिन के अंदर-अंदर नौकरी मिल जाएगी। इस फ्री ट्रेनिंग स्कीम में सरकार प्रशिक्षण देने के साथ-साथ नौकरी भी देगी। यह फ्री ट्रेनिंग कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) और National Institute of Solar Energy (NISE) की तरफ से चलाया जाएगा। इसे सोलर वाटर पम्पिंग “वरुण मित्र” कार्यक्रम कहा जाता है। इस ट्रेनिंग को करने का फायदा यह होगा की जो लोग नौकरी नहीं करना चाहते वे अपना खुद का रोजगार भी शुरू कर सकते हैं और जो अभी तक कम सैलरी पर काम कर रहे थे वे ज्यादा कमा सकेंगे। इस फ्री प्रशिक्षण सरकारी योजना में बेरोजगारों को रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर रिसोर्स असेसमेंट एव सोलर फोटोवोल्टिक, साइट फिजिबिलिटी, वाटर टेबल, सोलर वाटर पम्पिंग कंपोनेंट के अलग अलग प्रकार, डीटी कंवर्टर, इंवर्टर, बैटरी, मोटर्स, पम्प मोटर, इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड एंड स्टैंड अलोन सोलर पीवी वाटर पम्पिंग सिस्टम के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी।

96. उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन**अभियान लॉन्च की तारीख : 31 दिसम्बर 2018****उद्देश्य :** महिलाओं के लिए स्वच्छ व साफ सेनेटरी नैपकिन अभियान की शुरुआत

केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, सभी महिलाओं को राज्य के प्रत्येक जिले में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच मिलेगी। इस योजना में सरकार द्वारा महिला छात्रों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन पहल के पहले चरण में, तेल विपणन कंपनियां लगभग 100 स्थानीय विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करेंगी। ओएमसी इन इकाइयों को ओडिशा के 30 जिलों में 93 ब्लॉक में आम सेवा केंद्रों (सीएससी) में स्थापित करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : जल्द ही लॉन्च होगा

97. श्रेयस योजना**लॉन्च की तारीख : 27 फरवरी 2019****उद्देश्य :** छात्रों को नौकरी देने के लिए फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कीम

श्रेयस योजना के तहत, सरकार युवाओं को उद्योगों से जुड़ी हुई कौशल विकास और अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करेगी और उन्हें रोजगार प्राप्त करने और देश की प्रगति में योगदान देने में सक्षम करेगी। यह अवसर राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम (National Apprenticeship Promotional Scheme – NAPS) के माध्यम से अप्रैल 2019 में निकलने वाले सभी सामान्य स्नातकों पर लागू होगी। Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills (SHREYAS) योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को वज़ीफ़ा देने के साथ-साथ रोजगार से जुड़े अवसरों को बढ़ाना है। जिन छात्रों के पास डिग्री है उन्हें और अधिक कुशल, सक्षम, उद्यमी बनाना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। SHREYAS Scheme कार्यक्रम मुख्य रूप से डिग्री कर रहे छात्रों के लिए है जिनमें से मुख्य रूप से गैर-तकनीकी क्षेत्रों में पढ़ रहे छात्रों को रोजगार से जुड़ी सभी बातें बताना और उन्हें उद्यमी बनाने में सहयोग करना है। आधिकारिक वेबसाइट : shreyas.ac.in

98. प्रधानमंत्री जैव ईंधन – जीवन योजना**लॉन्च की तारीख : 28 फरवरी 2019****उद्देश्य :** वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण (JI-VAN) योजना | आधिकारिक वेबसाइट : finmin.nic.in

प्रधानमंत्री जीवन (जैव ईंधन – वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। JI-VAN योजना को 2018-19 से 2023-24 तक की अवधि के लिए 1969.50 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के लिए शुरू किया गया है।

99. जन धन खाताधारकों के लिए बीमा योजना**लॉन्च की तारीख : 15 फरवरी 2016****उद्देश्य :** जन धन से जन सुरक्षा प्रदान करना | आधिकारिक वेबसाइट : jansuraksha.gov.in

जन धन खाताधारकों के लिए बीमा योजना को जन धन से जन सुरक्षा योजना भी कहा जाता है। यह योजना 3 योजनाओं का मिश्रण है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें 330 रुपये के प्रीमियम से 2 लाख तक का सुरक्षा बीमा लिया जा सकता है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना जिसमें 12 रुपये के सालाना प्रीमियम से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा लिया जा सकता है और अटल पेंशन योजना जिसमें वृद्धावस्था के दौरान कम निवेश से ज्यादा लाभ मिल सकता है।

आधिकारिक वेबसाइट : mudra.org.in**100. प्रधानमंत्री आवास योजना लोन स्कीम****लॉन्च की तारीख : 2015****उद्देश्य :** मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणी के लोगों को सब्सिडी पर होम लोन प्रदान करना

मिग 1 के लिए 9 लाख तक के लोन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी @ 4% रुपये तक होगी और एमआईजी – II के मामले में 12 लाख के लोन पर 3 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी। हालांकि, बैंक 9-12 लाख से भी ज्यादा रुपये का होम लोन मंजूर कर सकते हैं। MIG के लिए PMAY CLSS के तहत, एक ब्याज सब्सिडी 20 वर्ष या ऋण के वास्तविक कार्यकाल के लिए, जो भी कम हो, के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि, बैंक अधिकतम 30 वर्षों के लिए ऋण मंजूर कर सकता है, लेकिन कर्ज लेने वाले को 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ऋण चुकाना पड़ता है।

आधिकारिक वेबसाइट : <https://homeloans.sbi/pmay> or respective bank websites**101. महिला सशक्तिकरण के लिए स्टार्ट-अप इंडिया योजना****लॉन्च की तारीख : 15 अगस्त 2015****उद्देश्य :** महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना

महिला उद्यमियों के लिए तत्काल मेंटरशिप प्रदान करना जिससे की वे अपने लिए स्वरोजगार खोल सके और साथ ही दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सके। स्टार्ट-अप इंडिया योजना से महिलाओं को एक डिजिटल मंच मिलेगा जहां पर वे अपनी स्किल को भी बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए और भी बहुत सी योजनाएँ चला रखी हैं जैसे की महिला ई-हाट कौशल प्रशिक्षण योजना आदि। आधिकारिक वेबसाइट : startupindia.gov.in